



याचिकाकर्ता ने क्या दिए तर्क?

याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा करने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उन्हें आर्थिक बहिष्कार के अधीन कर दिया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा दो और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश था और वे कहते हैं कि यह स्वीच्छिक है लेकिन वे इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। वकील ने कहा कि कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।

‘दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं’

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों से अपनी पहचान प्रदर्शित करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने इसे अल्पसंख्यक आबादी के लिए घातक बताया है। सीयू सिंह ने यह तक कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार का यह फैसला अल्पसंख्यकों के आर्थिक बहिष्कार की प्लानिंग का संकेत दे रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में NGO एसोशिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी है। इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है। इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सीयू सिंह दलील दे रहे हैं। वहीं वरिष्ठ वकील सिंघवी ने भी आपत्ति दर्ज की। वहीं कोर्ट ने इस मामले में न केवल यूपी बल्कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस भेजा और शुक्रवार को अगली सुनवाई तक के लिए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है, जिस पर वकील ने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि यह जमीनी हकीकत से ज्यादा बड़ जाए। इसके तीन आयाम हैं डू सुरक्षा, मानक और धर्मानिरपेक्षता और डू तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये बात जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कही जब सिंघवी ने कि ये पहचान का बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार है।

सावन के पहले सोमवार पर बिहार में हादसा, गंगा में चार लड़के डूबे



भागलपुर। भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर गंगा जहाज घाट पर नहाने के क्रम में सोमवार को डूबने से चार लड़कों की मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से तीन लड़कों के शव नदी से निकाल कर परिजनों को सौंप दिया गया है। एक की खोजबीन जारी है। मरने वाले सभी नवगण्डिया थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले हैं। परिजनों ने बताया कि पहली सोमवारी को लेकर नवगण्डिया नया टोला गांव से 11 लड़के गंगा स्नान के लिए मधुरापुर गंगा जहाज घाट

15 साल के ट्रेंड जवान को जॉब नहीं तो 4 साल के अग्निवीर को कैसे मिलेगी नौकरी : राहुल गांधी

नई दिल्ली। सेना में बतौर ‘अग्निवीर’ भर्ती हुए युवाओं को क्या चार साल बाद गारंटी से सरकारी नौकरी मिल पाएगी, इस बाबत सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को दस फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने इस आरक्षण के फ्रेमवर्क पर सवाल उठाते हुए कहा, अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, 2 करोड़ रोजगार की तरह एक जुगल है। जब मोदी सरकार 15 साल के प्रशिक्षित जवान को नौकरी नहीं दे पा रही, तो महज 4 साल के प्रशिक्षित अग्निवीर को नौकरी कैसे दे सकेगी। क्या 10वीं पास अग्निवीर युवा 4 साल बाद किसी सरकारी नौकरी का पेपर पास कर पाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद हुए संसद के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा



सरकार, संसद में श्वेत पत्र लेकर आए : चौधरी

चौधरी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि सेना में अग्निवीर जवान लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं। क्या अग्निवीरों को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है। क्या छह महीने का प्रशिक्षित अग्निवीर सेना में काम करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है। पिछले एक साल में कितने ‘सामान्य’ सैनिकों ने सुसाइड किया है। उक्त अवधि के दौरान कितने ‘अग्निवीर’ सैनिकों ने सुसाइड किया। सरकार, संसद में श्वेत पत्र लेकर आए कि अग्निवीर सैनिक व रेगुलर सैनिक में भेदभाव क्यों है।

उठाया था। उन्होंने अग्निवीरों को सेवा पेंशन से वंचित करने की आलोचना के दौरान ग्रेयुटी के अलावा अन्य लाभ न मिलने और उनके परिवार को कि सरकार अग्निवीरों को इस्तेमाल

न्यूज गैलरी

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई पूजा खेडकर की मां

पुणे। महाराष्ट्र में विवादों में घिरी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक किसान को धमकाने के मामले में आज मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर और पिता दिलीप खेडकर के अलावा चार अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें 2023 में मुलशी तहसील के धडवाली गांव में जमीन विवाद को लेकर एक किसान को बंदूक के जरिए धमकाते हुए देखा गया था।

वाल्मिकी घोटाले में पूर्व मंत्री नागेंद्र को झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्हें यहां की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें, अदालत ने यह फैसला महर्षि वॉल्मिकी विकास निगम में हुए कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में लिया है। बेल्छरी ग्रामीण



कांग्रेस विधायक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। आज उनकी हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां संघीय जांच एजेंसी ने और हिरासत की मांग नहीं की। कर्नाटक की महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम में लेखा विभाग के अधीक्षक चंद्रशेखर पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। इसके बाद निगम में बड़ा घोटाला सामने आया। नोट में निगम के खाते से 187 करोड़ रुपये अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए।

इसमें से 88.62 करोड़ रुपये आईटी कंपनी और हैदराबाद की एक सहकारी बैंक में अवैध रूप से भेजे गए। घोटाले का आरोप लगने के बाद अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने छह जून को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ईडी ने नागेंद्र से पूछताछ करने के बाद उन्हें 12 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था।

20 स्थानों की ली थी तलाशी

उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी ने इस महीने की शुरुआत में नागेंद्र और सतारूद कांग्रेस विधायक बासनगौड़ा के परिसरों सहित कई स्थानों पर तलाशी ली थी। एजेंसी ने घन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी।

‘भारत को कमजोर करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे’, ममता बनर्जी के बयान पर भड़की भाजपा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि सीएम राज्य में घुसपैठ को जायज ठहरा रही हैं। भाजपा ने यह आरोप ममता बनर्जी के उस बयान के बाद लगाया है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि वह बांग्लादेश के हिंसा प्रभावित लोगों को राज्य में शरण देने के लिए तैयार हैं। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की एकता को कमजोर करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



‘बंगाल की जनसांख्यिकी में आ रहे बदलाव’

रविशंकर प्रसाद ने तंज करते हुए कहा कि ‘टीएमसी की नया नागरिकता संशोधन कानून को विरोध कर रही हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता देता है, लेकिन वह घुसपैठियों की मदद करना चाहती है।’ प्रसाद ने ममता बनर्जी पर घुसपैठ को जायज ठहराने का आरोप लगाया और कहा कि ‘बंगाल में जनसांख्यिकी बदल रही है। राज्य में पहले मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या तीन थी, लेकिन आज यह बढ़कर नौ हो गई है। कोलकाता की जनसांख्यिकी में भी बदलाव आ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग कोलकाता आ रहे हैं।

‘शरण देने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास’

ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि वह चाहती हैं कि बंगाल के भारत के साथ अच्छे संबंध रहें। इस बयान पर हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने हैरानी जताई और कहा कि उनका कहना है कि क्या मतलब है? बंगाल तो भारत का ही हिस्सा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच कोलकाता में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंसा पीड़ितों को शरण देने के लिए बंगाल के दरवाजे खुले हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि किसी को शरण देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती।

एक नयी ‘नाम-पट्टिका’ पर लिखा जाए सौहार्दमेवजयते! : अखिलेश यादव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदार खाने का प्रकार लिखें और दुकानों पर उनका नाम लिखना जरूरी नहीं है। वहीं इस मुद्दे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है।



सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक नयी 'नाम-पट्टिका' पर लिखा जाए: सौहार्दमेवजयते!" इसके साथ ही अखिलेश यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए

NEET मुद्दे पर बोले अखिलेश

अखिलेश यादव ने NEET मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, "यह कैसे संभव है कि एक ही सेंटर पर इतने सारे छात्रों को इतने अंक मिलें। यह सरकार और उस संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है जो इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस सरकार ने पेपर लीक का एक रिकॉर्ड बनाया है।

लिए दुकाना के बाहर मालका को अपने नाम का बोर्ड लगाने को कहा है। सच तो यह है कि इसमें दिल्ली और लखनऊ की सरकारें एक साथ हैं।

आएगा। अपनी कुर्सी बचाने के

सूरज रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, यौन शोषण के आरोप में थे गिरफ्तार

बंगलुरु। यौन शोषण मामले में फसे प्रज्वल रेवन्ना के भाई और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) नेता सूरज रेवन्ना को बंगलुरु की एक अदालत से सशर्त जमानत मिली है। आपको बता दें कि सूरज रेवन्ना हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली उम्मीदवार हैं, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। साथ ही वे अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं।



था कि सूरज रेवन्ना ने 16 जून को घनोकाड़ा स्थित अपने फर्महाउस में शिकायतकर्ता का अप्राकृतिक यौन शोषण किया। शिकायत के आधार पर होलेनरसिपुरा पुलिस ने सूरज रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया।

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का किया समर्थन

वॉशिंगटन। अमेरिकी संसद में मौजूद पांच भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के फैसले की तारीफ की है, लेकिन इनमें से तीन ने ही कमला हैरिस को राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया है। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली उम्मीदवार हैं, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। साथ ही वे अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं।



ये भी डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े हैं। इनमें से अभी रो खन्ना, श्री थानेदार और प्रमिला जयपाल ने ही कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया है। भारतीय मूल के सांसदों में प्रमिला जयपाल ने सबसे

डेमोक्रेट पार्टी के कन्वेंशन पर टिकी निगाहें

जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद अगस्त में डेमोक्रेट पार्टी के नेशनल कन्वेंशन पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। अब कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। कन्वेंशन से पहले वरुणाली भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन सकती है। यदि कोई अन्य नेता राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करता है तो उसे कन्वेंशन में 600 पार्टी सदस्यों का समर्थन हासिल करना होगा। साथ ही कन्वेंशन में भी समर्थन जुटाना होगा। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो उनके बीच चुनाव होगा।

डेमोक्रेट पार्टी में प्रमिला जयपाल का कद बढ़ा है और वह पार्टी की मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं। प्रमिला जयपाल के अलावा भारतीय मूल के रो खन्ना और श्री थानेदार ने भी कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया।

तीनों सांसदों ने जो बाइडन की भी तारीफ की। इनके अलावा स्टेट सीनेटर सुहास सुब्रमण्यम ने भी कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन किया। अन्य सांसदों ने भी अभी खुलकर कमला हैरिस को समर्थन नहीं दिया है।

■ ■ न्यूज गैलरी

विकास लक्ष्य हासिल करने में तेजी से बढ़ता मध्यप्रदेश

भोपाल/नवप्रदेश। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में प्रस्तुत देश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में मध्यप्रदेश में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के नवाचारी प्रयासों का विशेष उल्लेख किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंदौर के 500 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाले बायोफयूल प्लांट का उल्लेख केस स्टडी के रूप में किया गया है। इसे 2021 में इंदौर नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्लांट आकल्पन-निर्माण-वित्त संचालन और हस्तांतरण के माडल पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर संचालित है। प्लांट करीब 44 से 45 हजार क्यूबिक मीट्ट बायो गैस प्रतिदिन बनाता है, जिससे करीब 17 हजार किलो बायो-सीएनजी प्रतिदिन बनती है। इस प्लांट से सालाना एक लाख तीस हजार टन कार्बन डायआक्साइड उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली है। इंदौर के बायो-सीएनजी प्लांट की प्रसंस्करण क्षमता 400 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इससे जैविक कचरे का प्रसंस्करण होता है, जिससे प्रतिदिन 14.8 मीट्रिक टन बायो-सीएनजी और 80 मीट्रिक टन फर्मेस्टेड जैविक खाद बनती है। इसके अलावा नदी जोड़ी परियोजना के अंतर्गत लिंक परियोजना का उल्लेख है जिसमें केन-बेतवा लिंक परियोजना, परिवर्तित-पार्वती-कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का उल्लेख किया गया है। केन- बेतवा लिंक परियोजना नेशनल पर्संपेक्टिव प्लान के अंतर्गत पहली परियोजना है जिसका अनुमोदन 2021 में किया गया था। इसके लिये केन्द्र सरकार की ओर से 39,317 करोड़ रुपये का सहयोग मिला है। इसे मध्यप्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के परस्पर सहयोग से क्रियान्वित किया जायेगा। सर्वेक्षण में नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इंडेक्स 2023-24 का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि जो दस नये राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने में आगे रहे हैं उनमें मध्यप्रदेश शामिल है। वर्ष 2018 से 2023-24 के बीच मध्यप्रदेश 15 अंकों के साथ सर्वाधिक तेजी से आगे बंते राज्यों शामिल है। सर्वेक्षण में किसान हितैषी नीति के फ्रेमवर्क का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की चर्चा की गई है। टीचिंग-लर्निंग और परिणाम को सुदृढ बनाने में मध्यप्रदेश ने सभी छह मापदंड पूरे किये हैं।

मंत्री डॉ. शाह ने मृगनयनी एम्पोरियम का निरीक्षण कर खरीदे परिधान

भोपाल/नवप्रदेश। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने सोमवार को वल्लभ भवन क्रं.-3 के भूतल स्थित मृगनयनी एम्पोरियम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एम्पोरियम के जरिये बेचे जाने वाले वस्त्रों व उत्पादों की जानकारी ली और प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री डॉ. शाह ने एम्पोरियम में प्रदर्शित वस्त्रों पर रुचि व्यक्त की और अपनी जरूरत व पसंद के अनुसार एम्पोरियम से परिधानों की नकद खरीदारी की। उन्होंने कहा कि हाथ से बने वस्त्रों की बात ही कुछ और है। यह आवश्यक होने के साथ टिकाऊ भी होते हैं। उन्होंने आगे भी यहीं से परिधान खरीदने की इच्छा व्यक्त की। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल को जब यह जानकारी मिली, तो उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनजातीय कार्य मंत्री से व्यक्तिन मिलकर उनका आभार व्यक्त करेंगे।

रीवा में कांग्रेसियों को वाटर कैनन से खदेड़ा: आंसू गैस छोड़ी, गुना में सीएम का पुतला जलाया

महिलाओं को जिंदा दफनाने के मामले में प्रदर्शन

रीवा/नवप्रदेश। रीवा में जमीन विवाद में दो महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश के मामले में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट घेरने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस भी छोड़ी। इसके बाद भी कांग्रेसियों के नहीं मानने पर हलका बल प्रयोग भी किया गया। बता दें कि मुरम कांड के विरोध में कांग्रेस रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकली थे, लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले ही उन्हें रोक दिया गया। वहीं गुना में भी कांग्रेस ने हनुमान चौराहे पर पानी डालकर उसे बुझाने की भी कोशिश की। इसका जवाब भी दिया गया। हालांकि, पुलिस ने जलते हुए पुतले पर पानी डालकर उसे बुझाने की भी कोशिश की।

जीतू पटवारी नहीं हुए शामिल

रीवा में आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय में उनका आना अस्थिर हो गया। प्रदर्शन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवासन, कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, बनिता पांडेय, वरिष्ठ नेता गिराश सिंह, कविता पांडेय, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी नागौद रश्मि सिंह पटेल, एनएसयूआई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी बैरिकेट्स तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते



रहे।

गुना में मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, हुई झड़प

रीवा में दो महिलाओं को मुरम डालकर जिंदा गाड़ने की कोशिश करने के मामले में गुना महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। स्थानीय हनुमान चौराहे पर नारेबाजी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला भी फूंका गया। हालांकि, पुलिस ने जलते हुए पुतले पर पानी डालकर उसे बुझाने की भी कोशिश की। इसके बाद कांग्रेसियों ने पुतले पर डंडे पर लातें मारीं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई।

रीवा में जमीन के झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की दो महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने हाइवा से महिलाओं पर मुरम डाल दी। इससे एक महिला कमर तक और दूसरी गले तक मुरम के

विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिये सरकार कोई कसर नहीं रखेगी : जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह

छात्रावासों में हों बेहतर व्यवस्थाएं, समान छात्रवृत्ति के लिये शीघ्र योजना प्रस्ताव बनाएं

व्यवस्थाओं एवं छात्रवृत्ति में एकरूपता लाने के लिये सुधार की प्रक्रिया तेज

भोपाल/नवप्रदेश। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि विद्यार्थियों के बेहतर व सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिये हमारी सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। प्रदेश के सभी छात्रावासों में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इससे विद्यार्थियों को वहां रहकर पढ़ाई करने और अपना भविष्य संवारने के लिये एक अच्छा सुकून भरा सकारात्मक परिवेश उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली अलग-अलग प्रकार की छात्रवृत्तियों में एकरूपता लाने और छात्रवृत्ति पाने के लिये विद्यार्थियों से मांगे जाने वाले दस्तावेज एवं छात्रवृत्ति स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये योजना का प्रस्ताव शीघ्र बनाया जाये। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने छात्रावासों में व्यवस्थाओं के सुदृढीकरण एवं छात्रवृत्ति में एकरूपता लाने के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित अंतर्विभागीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

बिजली उपभोक्ता सायबर जालसाजों से सावधान रहें-ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल/नवप्रदेश। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि बिजली उपभोक्ता सायबर जालसाजो से सावधान रहें। बिजली बिल का भुगतान कंपनी के अधिकृत गेट-वे अथवा कंपनी में कैश काउण्टर पर करें। कंपनी के संज्ञान में आया है कि सायबर जालसाजों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज अथवा आई.व्ही.आर. तकनीक से फोन कॉल कर नंबर दबाने हेतु कहा जाता है। इसमें बिल भुगतान करने हेतु भय बनाकर कहा जाता है कि आपकी बिजली कुछ घंटों बाद काट दी जाएगी, इसके लिए बिल भुगतान करने के लिये विशेष नंबर दबाएं अथवा मोबाइल नंबर विशेष पर संपर्क कर बकाया राशि जमा कराएं। इस प्रकार के एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज एवं आई.व्ही.आर. फोन कॉल फर्जी हैं। इन पर ध्यान नहीं दें। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस प्रकार के फर्जी सायबर जालसाजों से सतर्क और सावधान रहें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का नगद भुगतान कंपनी के जोन, वितरण केन्द्र कार्यालय, पीओएस मशीन अथवा अधिकृत भुगतान केन्द्रों जैसे एम.पी.ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, आईसेक्ट कियोस्क पर ही करें।



मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ करने की दिशा में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न शिक्षकों को मूल पदस्थापना में भेजकर उनसे सिर्फ अध्यापन का कार्य लिया जायेगा। इससे बच्चों की पढ़ाई और बेहतर होगी, साथ ही इसके गुणवत्तापूर्ण व सफल परिणाम भी सामने आयेंगे। बैठक में सभी विभागों के अधीन संचालित विभिन्न श्रेणी के छात्रावासों की वर्तमान स्थिति, निवासरत विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में मानव संसाधन व अधोसंरचनात्मक सुविधाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन छात्रावासों की स्थिति व विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्याश व केन्द्राश मिलाकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्तियां

दी जा रही हैं। इसके अलावा होनहार बच्चों को मेधावी छात्रवृत्ति योजना में भी लाभान्वित किया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति राशि के अंतर पर विचार कर एक समान छात्रवृत्ति के लिये प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव अपने स्तर पर बैठक कर योजना प्रस्ताव दें, ताकि अगली बैठक में इस पर पुनः विचार विमर्श हो सके।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के छात्रावासों में जरूरत के अनुरूप सुधार की प्रक्रिया तेज की जा रही है। छात्रवृत्ति भी पात्रानुसार दी जाती है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के अधिकाधिक विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ें। प्रोत्साहन राशि भी शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी दी जाती है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन भी सरकार द्वारा

प्रदेश में दुकान पर नेमप्लेट लगाने का कोई आदेश नहीं, सरकार की सफाई-चाहें तो स्वेच्छा से लगा सकते है



कोई स्वेच्छा से अपना नाम लिखना चाहता है तो लिख सकता है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नेमप्लेट विवाद को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार तक जवाब मांगा है।

विधायक मेंदोला ने की थी मांग

इंदौर से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में भी उत्तरप्रदेश की तर्ज पर कावड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली दुकानों के संचालकों के नाम लिखने का आदेश जारी करने की मांग की थी। इसके बाद उज्जैन महापौर मुकेश टेटवाल ने दुकान मालिकों को बोर्ड पर अपने नाम और फोन नंबर लिखने के निर्देश दिए थे। इसमें टेटवाल ने मेयर इन काउंसिल के फैसले का हवाला दिया था। इसमें दावा किया गया था कि प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था।

एकीकृत शाला निधि का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देश

राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी कलेक्टर को जारी किये निर्देश

भोपाल/नवप्रदेश। प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एकीकृत शालाओं की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिये एकीकृत शाला निधि का समुचित उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र दिशा-निर्देश जारी किये है। वार्षिक अनुदान अब शाला में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर जारी होगा। एकीकृत शाला निधि का उपयोग शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति के अनुमोदन के बाद किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। एकीकृत शाला निधि का उपयोग शालाओं की स्वच्छता, बस्तामुक्त, बालसभा, यूथ एण्ड इंको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र एवं स्कूल के आसपास की खोज जैसी गतिविधियों पर मुख्य रूप से किया जायेगा। इसके साथ ही शाला निधि का उपयोग खेलकूद और बालिकाओं के आत्म प्रशिक्षण पर भी मुख्य रूप से खर्च किया जायेगा। निर्देश में कहा गया है कि विद्यालय में ग्रीन बोर्ड छात्राओं के बैठने के लिये समुचित व्यवस्था, शालाओं की बुनियादी सुविधाओं पर आवश्यक खर्च और शालाओं में नियमित सफाई की व्यवस्था पर किया जायेगा। एकीकृत शाला में पढ़ने वाले छात्रों की पाठ्य पुस्तके और कॉपी वर्ष भर विद्यार्थियों के पास सुरक्षित रहें, इसके लिये शिक्षकों को इस जैसीबी लेकर पहुंचा था। उसके साथ में गोकर्ण प्रसाद पांडेय, विपिन पांडेय और महेंद्र पांडेय मौजूद थे। इन्होंने ही दोनों को धक्का मार कर गिराया था।

अगले सप्ताह मंगलवार को अपराह्न में इस समिति की पुनः बैठक आयोजित कर प्राप्त योजना के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाएगा।

14 सदस्यीय समिति गठित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अनुमूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के सरलीकरण एवं एकरूपता लाने छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार लाने पर अनुशंसा करने के लिये 14 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। समिति प्रदेश के सभी छात्रावासों में बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने तथा विभिन्न विभागों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की शिष्यवृत्तियों व छात्रवृत्तियों में एकरूपता लाने पर जल्द से जल्द विचार कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह अंतर्विभागीय समिति के अध्यक्ष बनाये गये हैं। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री समिति सदस्य बनाये गये हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, अपर मुख्य सचिव अनुसूचित जातिकल्याण, सचिव स्कूल शिक्षा तथा सचिव तकनीकी शिक्षा समिति के अन्य सदस्य और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य इस समिति के संयोजक सदस्य हैं।

वहीं, विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मॉडिया नियम 2017 के अंतर्गत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। इन बोर्डस पर नाम लिखने की कोई बाध्यता नहीं है।

कोर्ट का आदेश भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तत्परता से आदेश दिया है वह ऐतिहासिक है। धर्म के काम में अधर्म फैलाने की कोशिश कर रही भाजपा की सरकार के असंवैधानिक आचरण के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो शांति स्थापित करे, वही सरकार है, लेकिन इस मामले में तो प्रदेशों की चुनी हुई सरकारें घड़यंत्रपूर्वक अपने प्रदेशों के संवेदनशील हिस्सों के सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा दे रही थीं।

कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 10 और कक्षा 1 से 12 के रूप में निर्धारित की गई है।

शिक्षा सप्ताह पर हो रही है विशेष गतिविधियां

नई शिक्षा नीति-2020 की चौथी वर्षगांठ के मौके पर प्रदेश की शालाओं में 22 जुलाई से शिक्षा सप्ताह की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। यह गतिविधियां 28 जुलाई तक निरंतर जारी रहेंगी। गतिविधियों के तहत कक्षाओं में लघु नाटिका, कहानी सुनाना, जादुई पिटारा से संबंधित गतिविधियां हो रही है। सप्ताह के दूसरे दिन मूलभूत साक्षरता, विद्यार्थियों में पढ़ाई की प्रति रुचि, खिलौना प्रदर्शन, साक्षरता शिक्षा और फिल्म प्रदर्शन जैसी गतिविधियां होंगी। सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन सभी शालाओं में स्वदेशी खेलों की गतिविधियों को विशेष रूप से आयोजित किया जायेगा। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के मकसद से सांस्कृतिक विविधता पर केन्द्रित भाषा, वेशभूषा, खान-पान, लोकनृत्य और लोकगीतों की जानकारी दी जायेगी। सप्ताह के पांचवे दिन शाला के नजदीक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा। इसी दिन जैविक खेती, पशुपालन, सहकारी समितियों का भ्रमण, मिट्टी, शिल्प और बाँस जैसी सामग्रियों के महत्व के बारे में छात्रों को बताया जायेगा। सप्ताह के छठवें दिन प्रत्येक शाला में ईको क्लब के गठन के साथ ही प्रत्येक शाला में कम से कम 35 पौधे लगायें जायेंगे। छात्रों को इनके सुरक्षा की शपथ दिलाई जायेगी। सप्ताह के सातवें और अंतिम दिन सामूहिक महत्व के प्रयासों को बताने के लिये जागरूकता रैली का आयोजन मुख्य रूप से किया जायेगा।



बातों...बातों...में...!

साप्ताहिक स्तंभ

...सुकांत राजपूत

हर एक के पास 'देवराज' ...

हर एक के पास उनका मुंह लगा देवराज होता है। अब तो एकमात्र देवराज और जहांगीर आलम जैसे नौकर-चाकर ही हैं जो वफादार भी है और फर्मावरदार भी। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 25 करोड़ रुपए इंडी को मिले थे। मंत्री के पीए की जुठन उठाने वाले नौकर जहांगीर आलम की यह हैसियत तो फिर ड्राइवर 'देवराज' की हैसियत-हिम्मत का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बातों ही बातों में कांग्रेस के दबंग नेता का भरोसेमंद साथी की हिमाकत का एक किस्सा सामने आ गया। हालांकि मामला लोकसभा चुनाव के वक्त का है और घटना रायबरेली की। पैसों की कोई कमी नहीं और ताकत से लबरेज देवराज साथियों के साथ जमकर जाम छलकाया और जब गिलास भी समालाना मुश्किल हुआ, तो जिस होटल में उनका नेता रुका था उसी कमरे में जा घुसा। बाहर संतरी भी बेसुध था और कमरे में बिस्तर पर गहरी नींद में सुखीब के पर लगाकर नेता जी बिंदास लमलेट थे। बस देवराज भी उनके साथ एक ही रजाई में जा घुसा। जरा ठंड लगी तो अपने नेता की रजाई भी पूरी खींच ली। गनीमत था कि नशा फटा तो माजरा समझते ही कमरे से उठकर नौ दो ग्यारह हो ड्राइवर बिरादरी के साथ सो गया, लेकिन नेता जी जब उठे तो उनके होश उड़ गए, बिस्तर में देवराज का तौलिया देखकर... बस फिर क्या था माजरा, नजारा और मामला स्टाफ के लिए हर एंगल से चटकारेदार किस्सा बन गया।

सत्र के बाद दो मंत्री तो गियो...

कुर्सी के लिए बेकरार दो बीजेपी विधायक के लिए खुशखबरी है। उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है और उनकी मुराद भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल सत्र के बाद ही साय सरकार के दो पुराने मंत्रियों की बिदाई और दो नए की अगुवानी होने वाली है। बातों ही बातों में हॉउस के एक करीबी ने दावा किया है कि सबसे पहले राजस्व और महिला बाल विकास विभाग से रवानगी तय है। इसका सीधा मतलब है कि खट्टर ने जब महिला विधायक को मंत्री कर दिया था उस वक्त उनकी जुबान में सरस्वती वास कर रही थी। राजस्व ऐसा पेचीदा विभाग है जिसमें किसी अत्यधिक ज्ञानचंद जैसा विधायक और किसी तेजतर्रट मंत्री के पीए जैसी नियमों की जानकारी हो। ऐसे में सभी कुरद के दाऊ को ही इसके लिए सही दावेदार मानते हैं। अगर ऐसा है भी तो सवाल उठना लाजमी है... धरम, अमर, राजेश का फिर क्या होगा..?

हॉउस में रसूखदारों को भी ना...

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी के कार्यकाल में सीएम हॉउस में मोबाइल पर कोई खास पाबंदी नहीं थी। फिर आया रमन राज तो पहले कालखंड तक सबकुछ सरल और सहज था, दूसरे कालखंड में जरा सी सख्ती थी, लेकिन कम से कम साइलेंट मोड में खास लोग रखते थे। तीसरे में तो डॉक्टर साहब जैसे सरल, सहज को चुनिंदा लोगों ने सब से दूर कर दिया और मुलाकातियों को भी महसूस होने लगा था कि शुक है वो इंसान हैं कोई मोबाइल नहीं..! इस बार गरीब, किसान, आदिवासी और सबसे सरल मुख्यमंत्री जनता को मिला है। पहनावे से लेकर बोलचाल में भी उनकी सरलता दिखती है, लेकिन हाल ही में सुरक्षा में तैनात स्टाफ मोबाइल से सख्त गुरेज कर रहा है। फिर चाहे वो बीते कार्यकाल के कितने भी करीबी हो सभी का मोबाइल ले लिया जाता है। हॉउस में सिर्फ साहब के दो करीबी स्टाफ ही मोबाइल रखते हैं। एक दिवली से साथ काम देख रहे भाई और दूसरे गृहक्षेत्र के सबसे भरोसेमंद साथी। खैर सुरक्षा के लिए यह जरूरी है, लेकिन हाल ही में एक रसूखदार का भी मोबाइल जमा करने के बाद यह चर्चा आम है।

भूपेश से मिलने पहुंचे भगत...

भूपेश जब 'सरकार' में थे तब भी सबसे आसान था उनसे मिलना, लेकिन अब उनसे मुलाकात करना उतना आसान नहीं। खासकर फर्स्ट हाफ में उनकी दिनचर्या सरकार जाने के बाद अब ज्यादा मसरूफियत भरी है। एक वो भी वक्त था जब अमरजीत भगत उनके सबसे करीबी, चेहरे और क्या-क्या बन गए थे हमारे पास शब्द भी नहीं। सरगुजा पैलेस से दूर होकर पाटन हॉउस के करीब आने के बाद मंत्री पद से नवाजने वाले भूपेश से भगत नहीं मिल पाए। हाल ही में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भूपेश दाऊ से मिलने पहुंच गए। अंदर से खबर आई कि बैठने बोले हैं, भगत बैठे भी और ऐसे बैठना पड़ा कि बैठे-बैठे झुनझुनी चढ़ गई। उनको करीब दो घंटे से ज्यादा देर तक इंतजार करने के बाद भगत बिना मिले ही चले गए। खैर ऐसा क्यों और कैसे हुआ यह समीक्षा का विषय है, लेकिन एक बंगला स्टाफ ने बताया कि दाऊ जी योग, फिटनेस, स्नान फिर पूजा-पाठ खूब करने लगे हैं। हमने पूछा किसकी पूजा करते हैं.. तो खुलासा हुआ स्नान करके दाऊ जी सीधे पूजा कक्ष में जाते हैं और शिवलिंग का स्नान कराकर करीब एक घंटे पूजा करते हैं। वैसे भी दाऊ जब सरकार में नहीं थे तब भी उनके जानने वालों को पता है घर में वे जब तक अपना योग, स्नान, पूजा और फिर आराम से नाश्ता नहीं कर लेते तब तक इतनी आसानी से मिलने की जल्दी नहीं करते। वैसे भी भगत कोई राहुल, सोनिया या प्रियंका थोड़े न हैं...

अपने विचार नव प्रदेश की वेबसाइट www.navpradesh.com पर भेजें!

बिजली विभाग तारों के पास की झाड़ियों को हटाएं, शिकायतों का करें त्वरित समाधान

कलेक्टर ने राजस्व विभाग को आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का हल्केवार समीक्षा करने के लिए निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। शासन ने तहसीलदारों को जमीन संबंधी त्रुटि सुधार करने की जिम्मेदारी दी है, वे इससे जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें, इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। आरबीसी 6-4 के प्रकरण किसी भी स्थिति में लंबित न रहें। प्रत्येक तहसीलदार हल्के स्तर पर इसकी मीटिंग लेकर समीक्षा करें और समय पर हितग्राही को इसका लाभ दें। यह बात कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने समय-सीमा की बैठक में



कही। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम यह सुनिश्चित करें बिजली विभाग खुले हुए बॉक्स को बन्द करें और शहर के जिन स्थानों में झाड़ियां इत्यादि से तारों के टूटने का खतरा है उन्हें जल्द हटाएं। बिजली से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण करें।

कलेक्टर ने कहा कि सड़कों पर जहां कहीं भी निर्माण सामग्री फैली हुई हो जिससे यातायात बाधित हो रही हो उसको तत्काल हटवाया जाए और कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने गौठनों में किए गए अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए। डॉ सिंह ने कहा कि डायरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के फैलाव के नियंत्रण के उपाय किए जाएं जहां भी इससे जुड़ी सूचना मिलती है उस पर नजर रखें और तत्काल इलाज की व्यवस्था कर दवाईयां वितरित की जाए। खाद बीज इत्यादि की उपलब्धता बनाए रखें और इसका वितरण भी करें। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अंबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत की सीईओ श्री विश्वदीप, सभी एडीएम-एसडीएम उपस्थित थे।

कलेक्टर ने सुनी समस्याएं



रायपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कलेक्टर डॉ. सिंह ने रेडक्रॉस सभाकक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए तत्काल अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। राजातालाब निवासी श्री अब्दुल सलिम ने आवारा मवेशी के विचरण करने की शिकायत की। इस पर तत्काल कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए और तत्काल मवेशियों को हटाने को कहा। कैलाशपुरी निवासी श्री प्रमोद देवांगन ने पेड़ कटवाने के लिए, बंजारी रोड निवासी श्री रंजेंद्र गिरिपुंजे ने उचित न्याय दिलाने, पंडरी निवासी चित्तरंजन ने अपराधिक घटना के संबंध में शिकायत की। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अंबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर शुरू

अब 24 घंटे ऑनलाइन दर्ज करा सकेगे शिकायत, त्वरित होगा निराकरण

रायपुर/नवप्रदेश। अब जिला प्रशासन के कॉल सेंटर के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकेगे। यह सुविधा 24 घंटे मिलेगी और त्वरित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबरी भी जारी किया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर के कमरा नंबर 4 में जनसमस्या निवारण कॉल सेंटर निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अंबिनाश मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, संयुक्त कलेक्टर सूर्यो अभिलाषा पैकरा उपस्थित थे। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कॉल सेंटर से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। शहर से संबंधित, राजस्व व अन्य विभागों के मामलों की जानकारी फोन कॉल के माध्यम से दे सकते हैं। जानकारी प्राप्त होने के



तत्पश्चात जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा कॉल सेंटर में मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584, 9977222594 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। इस कॉल सेंटर में दिव्यांग भी अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हैं। दिव्यांगों की समस्याएं वीडियो कॉल में सांकेतिक माध्यम से सुने जाएंगे।

ऐसे होगा शिकायतों का निवारण

● हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आवेदक कॉल कर अपनी समस्या शिकायत दर्ज कराएंगे।

- कॉल सेंटर की टीम शिकायतकर्ता व आवेदक से बात करती है, उनकी समस्या सुनती है और उसे कॉल सेंटर के पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे।
- केस दर्ज करने के बाद व्हाट्सएप के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को मामले की जानकारी भेजी जाएगी।
- प्रकरण का त्वरित निराकरण किया जाएगा
- जब तक शिकायत का निराकरण नहीं होता, तब तक कॉल सेंटर समस्याओं पर संबंधित विभाग एवं अधिकारी से फॉलोअप करेगा।
- समस्या के निराकरण हो जाने पर आवेदक को कॉल करके सूचित किया जाएगा और पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान

सूचना आयोग में किया गया वृक्षारोपण



रायपुर/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के परिसर में आयोग के सचिव गोपाल वर्मा सहित उप सचिव श्रीमती आभा तिवारी, अवर सचिव गीता दीवान, अतुल वर्मा, प्रदीप गौर,

श्रीमती रजनी सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण में आम, अमरूद, जामुन, करीदा, अनार, पीपल, बड़, नीम, सीताफल, सन्तरा, आंवला, चीकू, नीबू आदि फलदार पौधों के साथ ही पारिजात, मोगरा, कचनार, मधुमालती गुलमोहर आदि फूलों के पौधे लगाए गए। इस दौरान सूचना आयोग के कर्मचारियों ने पौधों को अपनी माँ को समर्पित कर पौधों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया।

ईएनटी विभाग ने कॉक्लियर इम्प्लान्ट वाले दो मेधावी छात्रों का किया सम्मान

रायपुर/नवप्रदेश। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित नाक कान गला रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. (प्रो.) हंसा बंजारा ने ईएनटी विभाग के अंतर्गत सफलतापूर्वक किए गए कॉक्लियर इम्प्लान्ट के पश्चात् शैक्षणिक क्षेत्र में सफल एवं शानदार प्रदर्शन के लिए दो मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इनमें से भावना पटेल ने कक्षा 10 वीं में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है एवं आदित्य तिवारी ने बी. एस. सी. (गणित) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। डॉ. हंसा बंजारा एवं



टीम ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा अभूतपूर्व प्रयासों के लिए उन्हें भेंट देकर प्रोत्साहित किया। डॉ. हंसा ने बताया कि ये बच्चे कॉक्लियर इम्प्लान्ट श्रवण यंत्र का इस्तेमाल करते हैं और इसकी सहायता से इन्हें सुनने में मदद मिलती है। इन बच्चों ने समाज को यह साबित कर दिखाया है कि सही समय रहते इम्प्लान्ट का (गणित) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। डॉ. हंसा बंजारा एवं

न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.बी.बाजपेयी दूसरी बार पहुंचे बलोदाबाजार

बलोदाबाजार/नवप्रदेश। जिले के ग्राम महकोनी स्थित अमर गुप्त में जैतखाम तोड़े जाने की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सी बी बाजपेयी आज दूसरी बार बलोदाबाजार पहुंचे। उन्होंने आज बैठक कर आयोग कार्यालय के लिए अधिसूचना एवं प्रक्रियाविनियम को अंतिम स्वरूप प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किया गया है। ताकि आने वाले दिनों में



अधिसूचना राजपत्र सहित दैनिक समाचारों में प्रकाशित हो सके। इसके साथ ही श्री बाजपेयी ने कार्यालय के बाहर आयोग कार्यालय संबन्धित

बोर्ड लगाने, कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आयोग के सचिव को दिए हैं। गौरतलब की राज्य शासन द्वारा 15 मई व 16 मई 2024 के मध्यरात्रि को जिला बलोदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत ग्राम महकोनी,अमरगुप्त में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किये जाने की घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है।

देसंवि वि के नवीन शैक्षणिक सत्र की हुई शुरुआत

युवा अनुशासन का निर्वहन करें: रावत

ज्ञानदीक्षा ज्ञान के उदय का पर्व : डॉ चिन्मय पण्ड्या

हरिद्वार/नवप्रदेश। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज का 44वां ज्ञानदीक्षा समारोह उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत, विशिष्ट अतिथि दून विवि की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, देसंवि वि के कुलपति शरद पारधी, प्रतिकुलपति डॉ चिन्मय पण्ड्या द्वारा दीप प्रज्वलन एवं देसंवि वि के कुलगीत से हुआ। ज्ञानदीक्षा समारोह में भारत के 15 राज्यों के नवप्रवेशी छात्र छात्राएं दीक्षित हुए। समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि जिन युवाओं में अनुशासन होता, ऐसे



युवा ही आगे बढ़ते हैं। देसंवि वि की एक खास बात है कि यहाँ युवाओं को अनुशासन के निर्वहन के लिए हमेशा प्रशिक्षित करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति हमें जड़ों से जुड़ना और अनुशासित रहना सिखाता है। श्री रावत ने कहा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला ज्ञानदीक्षा संस्कार समारोह एक बहुत ही अच्छा आयोजन है, जिसे राज्यभर के सभी विश्वविद्यालयों में आयोजित किया

जाना चाहिए, जिसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय को एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ज्ञानदीक्षा संस्कार समारोह जैसे कार्यक्रमों के साथ जब विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में आगमा, तो रैगिंग जैसी परेशानियों की जड़ से खत्म हो जाएंगी। विशिष्ट अतिथि दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि शिक्षा भौतिक जगत से परिचित कराता है, लेकिन विद्या जड़ से जगत की यात्रा कराता

ज्ञान के उदय का पर्व है। कुलपति शरद पारधी ने स्वागत भाषण दिया। इससे पूर्व मंत्री धनसिंह रावत, प्रो सुरेखा डंगवाल ने वीर शहीदों की याद में बने शौर्य दीवार पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज के 44वां ज्ञानदीक्षा संस्कार समारोह में नवप्रवेशी विद्यार्थी वैदिक सूत्रों में बंधे। समारोह में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मप्र, झारखंड, बिहार सहित 22 राज्यों के 2000 से अधिक छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे। उदयकिशोर मिश्र व रामावतार पाटीदार ने नवप्रवेशार्थी छात्र-छात्राओं को वैदिक रीति से ज्ञानदीक्षा का वैदिक कर्मकाण्ड कराया। वहीं चर्यानिर्त विद्यार्थियों को अतिथियों ने देसंवि वि के प्रतीक चिह्न भेंट किया। समापन से पूर्व मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कुलपति एवं प्रतिकुलपति ने ध्वनन्तरी सहित अनेक पत्रिकाओं का विमोचन किया। इस अवसर पर देसंवि वि के कुलसचिव

■ न्यूज गैलरी

अमानक चावल की अनलॉडिंग पर परिवहन कर्ता से 18.71 लाख रुपये वसूली के निर्देश

भोपाल/नवप्रदेश। खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर शिवपुरी जिले में अमानक चावल की अनलॉडिंग पर वर्षा से प्रभावित 913 बोरे चावल की लागत 18 लाख 71 हजार रुपये की वसूली संबंधित परिवहन कर्ता से करने के निर्देश दिये गये हैं। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री पी.एन. यादव ने जानकारी दी है कि शिवपुरी जिले के गोदामों में पाये गये 4 स्टेक बीआरएन चावल एवं सतना जिले में 6 स्टेक बीआरएल चावल बदलकर मानक चावल जमा करने हेतु सतना जिले के 5 मिलर्स मेगनेश राईस मिल, सक्षम राईस मिल, शिवशक्ति राईस मिल, लाल कन्हैया राईस मिल एवं कुष्णा राईस मिल को नोटिस जारी किये गये हैं। शिवपुरी एवं सतना जिले में जमा चावल के बोरो में टैग / स्टैम्पिल लगे न होने, पुराने बारदानो में डेमेज, डिस्कलर एवं अधिक ब्रोकरन वाले जमा चावल में संबंधित 12 मिलर्स मेगनेश राईस मिल, अनाज भंडार राईस मिल, कमलादेवी राईस मिल, हाईटेक राईस मिल, नमन राईस मिल, एम.के.बी. राईस मिल, सक्षम राईस मिल, लाल कन्हैया राईस मिल, शिवशक्ति राईस मिल, जय कामतानाथ राईस मिल, कुबेर फूड राईस मिल एवं ओशियन राईस मिल को नोटिस जारी किया गया है। बीआरएल चावल जमा कराये जाने के संबंध में सर्वेयर एंजेंसी मेसर्स ब्यूरो बेरीटएस प्रायवेट लिमिटेड मुंबई को भी नोटिस जारी किया गया है। सतना जिले के जिला प्रबंधक श्री पंकज बोरेसे एवं कॉर्पोरेशन के 2 केंद्र प्रभारी श्री सुनिल गंग एवं श्री जी.एल. गुप्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं भविष्य में चावल भंडारण के लिये उपयुक्त गोदामों में ही चावल जमा कराये जाने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा गया है।

एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगो को लेकर धरना दिया

भोपाल/नवप्रदेश। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश में एचएम कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। इनका कहना है कि हम अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं कई सरकार बदली लेकिन अभी हमें तक नियमित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि हमारा वेतन भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर में बताया कि संविदा कर्मचारियों के लिए 2023 में संविधान नीति बनाई गई थी इसका फायदा अभी तक नहीं मिला है। यहां आकर अनुकंपा नियुक्ति की मांग भी रखी गई है। यहां एचएम कार्यालय के पास दिव्यांगत संविदा कर्मचारियों की श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई। सोमवार को प्रदेश के करीब 70 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एचएम कार्यालय के बारे में धरना प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दे डाली की अगर उनकी मांगे पूरी नहीं है बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के करीब 32000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी एनएचएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। दोपहर में ही उन्होंने एचएम कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन दिया है जानकारी के अनुसार सोमवार को प्रदेश के करीब 32000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी समूहकि अवकाश पर रहने की सूचना है। इस कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप रही। इस कारण लोगों को पेशेनामी का सामना भी करना पड़ा है। कई संविदा स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य केंद्र पर काम पर नहीं गए हैं।

बूथ स्तर पर जानकारी जुटा रही कांग्रेस, जीतू ने जिला प्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों से की वन-टू-वन चर्चा

एमपी में लोकसभा और विधानसभा में मिली हार को लेकर कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर कारण तलास रही है। इसे लेकर पीसीसी में जिला ब्लॉक प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई।

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब बूथ स्तर पर हर के कारणो की जानकारी जुटा रही है। सोमवार को पीसीसी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल संभाग के जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों-सहप्रभारियों, ब्लॉक अध्यक्षों एवं उपब्लॉक अध्यक्षों के साथ जिलेवार संगठनात्मक बैठकों ली। इस दौरान पार्टी में जमीनी स्तर पर व्याप्त गुटबाजी को भी हार की बड़ी वजह बताया गया। इतना ही नहीं चुनाव से पहले राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हुए दल-बदल ने भी पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। यह बात कई पदाधिकारी ने बैठक में चर्चा के दौरान कही है। साथ ही आगामी समय में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने पर भी कई नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की। बैठक में आगामी समय में होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा हुई। भोपाल संभाग के सीहोर जिले की बुधनी सीट में भी आगामी समय में उपचुनाव संभावित है। दो दिन पहले राजनीतिक मामलों की समिति की भी भोपाल में बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए थे। इस बैठक में संगठन को और मजबूत

उप-मुख्यमंत्री शुक्ल ने हिनौती ग्राम में गौवंश वन्य विहार के विभिन्न कार्यों का किया भूमिपूजन एवं लोकार्पण

1 हजार 303 एकड़ क्षेत्र में विकसित गौवंश वन्य विहार अब कहलायेगा गौधाम

25 हजार गौवंश को मिलेगा संरक्षण

भोपाल/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत हिनौती ग्राम में 1 हजार 303 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे गौवंश वन्य विहार में विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 25 हजार गौवंश को संरक्षण मिलेगा। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह गौवंश वन्य विहार गौधाम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का दिन अत्यंत शुभ है। श्रावण मास के प्रथम दिवस में भगवान शिव के आशीर्वाद से गौवंश के संरक्षण के पुनीत कार्य में हम सभी भागीदार बन रहे हैं। गौ माता पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। उन्होंने अपील की गौवंश संरक्षण हेतु आयोजित यज्ञ में सभी अपनी भागीदारी निभाएं।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने 65.64 लाख रुपए से निर्मित दो गौ शेड का लोकार्पण करने के उपरांत गौ पूजन किया तथा गाय को चना एवं गुड़ खिलाया। उप



मुख्यमंत्री ने 71.50 लाख रुपए के कार्यों का भूमिपूजन किया। जिनमें 30.42 लाख रुपए की लागत से दो नग गौ शेड, 21.92 लाख रुपए की लागत से चारागाह क्षेत्र की तार फेंसिंग, 15.16 लाख रुपए की लागत से दो हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास तथा चार लाख रुपए लागत के सामुदायिक स्वच्छता परिसर का कार्य शामिल है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की मंशा के अनुरूप

20 से 25 हजार गौवंशों को मिलेगा संरक्षण

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार के बाद हिनौती का गौवंश वन्य विहार गौ संरक्षण के लिए प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध केन्द्र होगा और लोग इसको देखने आएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गौवंश वन्य विहार में 25 हजार गौवंशों को संरक्षण मिलेगा तथा आसपास के गांवों के गौ-सेवकों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। श्री शुक्ल ने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की तथा निर्देश दिए कि सभी कार्य तत्काल प्रारंभ करा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आने वाले समय में यह आत्मनिर्भर व अन्य गौशालाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाला गौवंश वन्य विहार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी गौवंश के पोषण आहार के लिए प्रति गाय प्रति दिवस की राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है।

उप-मुख्यमंत्री ने किया वृक्षारोपण

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने गौवंश वन्य विहार परिसर में एक पेड़ मॉ के

एक हत्या करने के बाद दूसरी हत्या के इरादे से जा रहा था, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरदा/नवप्रदेश। 19 जुलाई की रात करताना निवासी 45 वर्षीय संतोष पिता महेश जाट की हत्या करने के बाद 44 वर्षीय आरोपित महेश पिता रामगोपाल जाट निवासी करताना एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने भोपाल जा रहा था। पुलिस ने उसे 20 जुलाई को गोदागांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने दूसरी हत्या करने भोपाल जाने की बात स्वीकारी। इसके बाद सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेसवार्ता में एसपी अभिनव चौकसे ने यह खुलासा किया। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि भोपाल के एक व्यक्ति ने लोन पास करवाने के लिए उससे राशि ली थी। लोन नहीं करवा रहा था, जिससे मैं बहुत परेशान हो चुका था। इसके बाद उसने संतोष को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। संतोष को मारने के बाद मैं भोपाल जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।

खाद्य मंत्री राजपूत ने मृतकों के परिजन को वितरित की 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि



भोपाल/नवप्रदेश। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत व्यक्तियों के परिजन को सहायता राशि वितरित की। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि घर के किसी भी व्यक्ति कि अचानक मृत्यु उस परिवार के लिए असहनीय कष्ट और पीड़ा दायक होती है जिसे कोई भी कम

धमेंद्र पटेल, जितेंद्र पिता बैजनाथ निवासी केवलारी, गणपत दागी, भगवान दास पटेल निवासी देहरा टिहरी, अखिलेश पिता गजई चंदार निवासी परगामपुरा की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर तथा कुमारी अवनी पिता रामकृष्ण कुर्मी निवासी हिनोद को सांप के काटने से मृत्यु होने पर मंत्री श्री राजपूत ने चार-चार लाख रुपए की राशि के चेक उनके परिजन को प्रदान किए।

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में खुलेंगे 94 सीएम राइज स्कूल

38 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण इसी साल पूरा कर इनमें पढ़ाई भी शुरू कर दी जायेगी

भोपाल/नवप्रदेश। प्रदेश के जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और इनके सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जनजातीय वर्ग के बच्चे शिक्षा के मामले में किसी से भी पीछे या कमतर न रहें, इसके लिये सरकार ने जनजातीय बहुल अंचलों/जिलों में इन बच्चों की बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की चिंता की है। इसके लिये सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 94 सीएम राइज स्कूल्स स्थापित करने का निर्णय लेकर इस पर काम भी प्रारंभ कर दिया है। इन विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक व शारीरिक विकास सहित खेल एवं अन्य विधाओं की शिक्षा भी दी जाएगी।

जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले 94 सीएम राइज स्कूल्स से वरतमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा कर इनमें जल्द से जल्द पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिये युद्ध स्तर पर स्कूलों का निर्माण एवं अन्य जरूरीविकासकार्य किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये सरकार ने जारी वर्ष के सालाना बजट में 667 करोड़ रुपये आरक्षित कर दिये हैं। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना, प्रोत्साहक परिवेश एवं

अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने सीएम राइज स्कूलों की स्थापना कर प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य बदलने का बोझ उठया है। प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की स्थापना के लिये सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 2 हजार 738 करोड़ रुपये प्रावधानित किये हैं।

पहले चरण में 275 प्रारंभ, आगामी 10 साल में 9200 सीएम राईज स्कूल खोलने की योजना

सरकारी स्कूलों में सर्व-सुविधायुक्त वातावरण के साथ विद्यार्थियों को रोजक आनंददायक शिक्षा देने के लिये सरकार ने सीएम राइज स्कूल्स की स्थापना की है। पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी 10 सालों में प्रदेश में 9 हजार 200 सीएम राइज स्कूल्स शुरू करने की सरकार की योजना है। इन सीएम राइज स्कूल में के.जी. से कक्षा 12वीं तक संचालन की व्यवस्था के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये डिजिटल कक्षा, पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, कला, नृत्य, संगीत एवं योग शिक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है।

स्कूलों में परिवहन की व्यवस्था
सीएम राइज स्कूलों में दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को सुविधा देने की मंशा से परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे स्कूल के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। सीएम राइज स्कूल में बेहतर नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से इन स्कूलों के प्राचार्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर में विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है। साथ ही प्राचार्यों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति-प्राप्त विद्यालयों में एक्सपोजर विजिट भी कराई गई है।

प्राचार्य हैण्ड-बुक

सीएम राइज स्कूलों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को वैश्विक-मानकों के अनुरूप पूरा करने के लिये प्राचार्यों और शिक्षकों के लिये अलग-अलग हैण्ड-बुक तैयार की गई हैं। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिये सीएम राइज स्कूलों में स्टूडेंट डायरी भी तैयार की गई है। विद्यार्थियों के विचार, चिंतन, मंथन एवं प्रभावी शिक्षण के लिये आवश्यक टूल्स को डायरी के पृष्ठों में शामिल किया गया है। इसके जरिये विद्यार्थियों की रचनात्मक गतिविधियाँ एवं उनकी शैक्षणिक प्रगति पालकों/अविभावकों को भी बताई जाएगी।